TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 229
दि. 20.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

हंगामे से शुरू हुआ सत्र चाय पर चर्चा से खत्म, पास हुए ये अहम बिल

(जीएनएस)।

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे और गतिरोध के बाद आखिरी दिन चाय पर चर्चा के साथ निपट गया। लोकसभा स्पीकर की ओर से दी गई चाय पार्टी में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस पूरे सत्र में चुनाव सुधार, एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष का विरोध और हंगामा होता रहा। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर दोनों सदनों में चर्चा हुई।

इस सत्र में हुई तीखी बहसों और टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी के साथ हुआ। पिछले सत्र में विपक्ष ने इस चाय पार्टी का विरोध किया था। हालांकि, इस बार कई विपक्षी दल के नेता इसमें शरीक हुए।

– संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में कुल 8 विधेयक पास हुए। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चला और इसमें लोकसभा की 111% तथा राज्यसभा की 121% उत्पादकता दर्ज की गई।

– 1 दिसंबर से शुरू हुए सत्र में हंगामे से लेकर बिल फाड़ने और टीएमसी सांसदों के धरना जैसे नाटकीय घटनाक्रम भी हुए।

– VB-G RAM G विधेयक, 2025, शांति (SHANTI) विधेयक, 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (डी२२) विधेयक, 2025, विनियोग विधेयक

(संख्या 4), 2025, निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 इस सत्र में पारित हुए।

– वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उलक्ष्य में सदन में 10 घंटे की चर्चा करानी गई। इस सत्र में चुनाव सुधारों पर भी संसद के दोनों सदनों में तीखी चर्चा हुई।

बिल फाड़ने से लेकर धरने तक की चर्चा

शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के साथ ही इस बार कई नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिले। विपक्ष ने मनरेगा बिल का नाम बदलने का तीखा विरोध किया। लोकसभा में बिल फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह के ऊपर कागज फेंक दिए। टीएमसी ने इस बिल के विरोध में आधी रात तक धरना भी दिया। हालांकि, इन सबके बावजूद इसे पास कराया गया। शांति बिल पर भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सत्र के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

सीएम योगी बोले- अखिलेश की माफिया के साथ तस्वीरें, जांच होने दीजिए...दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

लखनऊ (जीएनएस)। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन माफिया के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन-देन में संलिप्तता भी सामने आएगी। जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सपा प्रमुख की स्थिति वही है, 'यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।

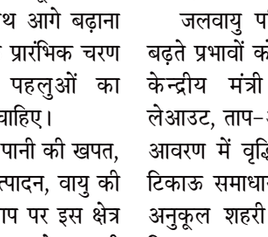

सपा पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही

शुक्रवार को सत्र के पहले दिन योगी ने सदन में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के हर माफिया के संबंध सपा से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध सपा से रहे हैं।

सपा अपनी कार्यप्रणाली के लिए पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही है। इस पूरे मामले में भी अपनी संलिप्तता उजागर होते हुए देखेगी। इस विषय में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोडीन फॉस्फेट एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एक औषधि है।

इसका उपयोग कोडीन-युक्त कफ सिरप के निर्माण में होता है। इसका कोटा और आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा केवल अधिकृत औषधि

राष्ट्रपति ने हैदराबाद में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

लोक सेवा आयोगों को न केवल अवसर की समानता के आदर्श से निर्देशित होना चाहिए, बल्कि परिणामों की समानता के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

लोक सेवा आयोगों को भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा और समग्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना के हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निमार्ताओं ने संविधान का एक पूरा भाग सेवाओं और लोक सेवा आयोगों को समर्पित किया है। यह केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की भूमिकाओं और कार्यों को दिए गए महत्व को दशार्ता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समान अवसर और प्रतिष्ठा के हमारे संवैधानिक आदर्श लोक सेवा आयोगों के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

संविधान की प्रस्तावना, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का मौलिक अधिकार और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देशित करने वाले निर्देशक सिद्धांत, लोक सेवा आयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक सेवा आयोगों को न केवल समान अवसर के आदर्श से निर्देशित होना चाहिए, बल्कि परिणामों की समानता के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लगभग 3200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, प्रधानमंत्री नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बाराजागुली-कृष्णनगर खंड पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बारासात-बाराजागुली खंड पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4-लेन की आधारशिला रखेंगे, ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे। सुबह लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे।

ऊर्जा की दृष्टि से किफायती डिजाइन, चक्रीय निर्माण पद्धतियों और हरित भवनों को अपनाएं: श्री भूपेंद्र यादव

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने सीआरईडीएआई राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में टिकाऊ एवं जलवायु के अनुकूल शहरी विकास पर जोर दिया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आयोजित कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) के राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, शहरी भविष्य और जीवन स्तर को आकार देने वाली राष्ट्र निर्माण शक्ति के रूप में रियल एस्टेट क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में नगर नियोजन एवं निर्माण में समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास एवं पर्यावरण संरक्षण परस्पर पूरक लक्ष्य हैं और इन्हें साथ-साथ आगे बढ़ाना होगा तथा नियोजन के प्रारंभिक चरण में ही पर्यावरणीय पहलुओं का समावेश किया जाना चाहिए।

ऊर्जा के उपयोग, पानी की खपत, अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन, वायु की गुणवत्ता और शहरी ताप पर इस क्षेत्र के प्रभाव को रेखांकित करते हुए, श्री यादव ने कहा कि रियल एस्टेट भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं का केन्द्रबिंदु है, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि स्थिरता अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार विकास की नींव है।

जलवायु परिवर्तन के शहरों पर बढ़ते प्रभावों को रेखांकित करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने बाढ़-प्रतिरोधी लेआउट, ताप-अनुकूल सामग्री, हरित आवरण में वृद्धि और आवागमन के टिकाऊ समाधानों सहित जलवायु के अनुकूल शहरी नियोजन का आ'ान किया।

केन्द्रीय मंत्री ने पर्यावरण संबंधी प्रशासन को आधुनिक बनाने हेतु मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें पर्यावरण मंजूरी तंत्र को मजबूत करना, डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों को बढ़ावा देना, जोखिम-आधारित नियामक दृष्टिकोण को अपनाना, मिशन लाइफ एवं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में वायु एवं पानी की गुणवत्ता ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल है।

उद्योग जगत के हितधारकों को आश्वस्त करते हुए, श्री यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुपालन को दक्षता के साथ पुरस्कृत करना और उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार करने में सुगमता पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर नहीं आ सकती और न ही पर्यावरण संरक्षण अनावश्यक देरी का कारण बनना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र को ऊर्जा की दृष्टि से किफायती डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा, पानी की दृष्टि से सकारात्मक विकास, चक्रीय निर्माण पद्धतियों और हरित भवनों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो शहरों और नागरिकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करते हैं।

18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन दर 111 प्रतिशत रही : लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला

छठे सत्र के दौरान लोकसभा की 15 बैठकें हुईं, जो 92 घंटे 25 मिनट तक चलीं: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा में 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 8 विधेयक पारित हुए: लोकसभा अध्यक्ष

वंदे मातरम पर चर्चा 11 घंटे 32 मिनट तक चली और इसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया: लोकसभा अध्यक्ष

चुनावी सुधारों पर 13 घंटे तक चर्चा हुई और इसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया : लोकसभा अध्यक्ष

सत्र के दौरान सार्वजनिक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण 408 मामले उठाए गए: लोकसभा अध्यक्ष

(जीएनएस)।

अठारहवीं लोकसभा का छठा सत्र आज समाप्त हो गया। यह सत्र 1 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था।

इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने जानकारी दी कि सत्र के दौरान 15 बैठकें आयोजित की गईं। सत्र के दौरान कुल बैठक का समय 92 घंटे और 25 मिनट था।

श्री बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की कार्यनिष्पादन दर 111 प्रतिशत रही।

सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 8 विधेयक पारित किए गए। पारित विधेयक निम्नलिखित हैं:

(i) मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025;

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025;

(iii) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025;

(iv) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025;

(v) निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025;

(vi) सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025;

(vii) भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं संवर्धन विधेयक, 2025; और

(viii) विकसित भारत – रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025

15 दिसंबर, 2025 को चर्चा के बाद, अनुदान के लिए पूरक मांगों – प्रथम बैच, 2025-26 पर मतदान हुआ। इसके बाद, विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

8 दिसंबर, 2025 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक चर्चा का आयोजन किया। सदन ने इस विषय पर 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया। इसी प्रकार, 9 और 10 दिसंबर को "चुनावी सुधार" के मुद्दे पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया।

सत्र के दौरान 300 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए और 72 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

ऊर्जा स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और भू-राजनीतिक अनुकूलता के अनुरूप: डॉ. जितेंद्र सिंह

'डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे कुछ क्षेत्रों को निर्बाध, स्थिर, चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली की आवश्यकता होती है, जहां परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है'

भारत पीछे नहीं चलेगा; यह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में विश्व का नेतृत्व करेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

स्वच्छ ऊर्जा अब केवल एक नीतिगत बहस नहीं, बल्कि जीवन शैली है: डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथि: 19 ऊएउ 2025 5:04ढट्ु८ ढक्ह ऊ्'

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा स्वतंत्रता अब विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक आर्थिक, रणनीतिक और भूराजनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ और विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत का संक्रमण आत्मनिर्भरता और भूराजनीतिक अनुकूलता, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने पर होने वाली बहसें अब निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर यह सर्वमान्य है कि सतत विकास, आर्थिक मजबूती और भू-राजनीतिक अनुकूलता के लिए ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा, "यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने से न केवल आत्मनिर्भरता मजबूत होती है, बल्कि भारत अपरिहार्य वैश्विक बदलाव के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा निर्यातक देश स्वयं तेजी से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पुराने ऊर्जा मॉडलों पर टिके रहना पुरानी तकनीक से भावनात्मक रूप से चिपके रहने जैसा है, कल तो उसके पुर्जे भी नहीं मिलेंगे।'

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि देश अब निष्क्रिय भागीदार नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत अब वैश्विक रुझानों का अनुसरण नहीं कर रहा है; आज अन्य राष्ट्र मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं।' उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारतीय नवाचार वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचा रहा है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा की थी और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के सरकार के संकल्प को दोहराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को भेदभाव के नजरिए से नहीं, बल्कि उपयुक्तता, विश्वसनीयता और विशिष्ट अनुप्रयोग में उनकी उपयोगिता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

सम्पादकीय

कार्यकारी अध्यक्ष क्यों

राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय जनता पाटा ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को पाटा का नया कायंकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सबको चौंका दिया है। शायद ही किसी ने उम्मीद की हो कि नबीन बाबू को इतना महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। पिछले कई महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनने वाली है क्योंकि श्री नड्डा का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका था और वह एक्सटेंशन पर चल रहे थे। नितिन नबीन भाजपा के इतिहास में जेपी नड्डा के बाद दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। पाटा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई औपचारिक पद नहीं है। लेकिन साल 2019 के बाद से भाजपा में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की एक परंपरा शुरू हुई है। भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब होगा अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में पाटा के शीर्ष नेताओं के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी में ये प्राव्रिया पूरी की जा सकती है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी जनवरी तक ही है। ऐसे में से सवाल उठ रहा है कि जब वुछ दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है तो पाटा ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है? इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है लेकिन ये माना जा रहा है कि पाटा अपने संविधान के हिसाब से होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को आम सहमति और निर्विरोध रूप से करना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि भाजपा जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्राव्रिया शुरू करेगी। पाटा में इसकी एक औपचारिक प्राव्रिया है। ऐसे तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन नामांकन तिथि, चुनाव तिथि में औपचारिक प्राव्रियाएं हैं, पाटा को इन्हें करना है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं, कायंकारी अध्यक्ष घोषित कर भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि नितिन नबीन ही अगले अध्यक्ष होंगे। भाजपा में अध्यक्ष को चुनने की एक लंबी प्राव्रिया है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन सिन्हा को पाटा का कायंकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने जाने वाले नितिन नबीन 5 बार से लगातार विधायक हैं और भाजपा के पहले कायंकारी अध्यक्ष हैं। 45 साल के नितिन नबीन का कायंकारी अध्यक्ष बन जाना जरूर कई लोगों को हैरान कर रहा है लेकिन विश्लेषक इससे हैरान नहीं हैं। बिहार चुनावों के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन से दो घंटे मुलाकात की थी। नितिन नबीन पाटा के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के प्राभारी थे और भाजपा ने यह चुनाव भारी बहुमत से जीता था। यानी नितिन नबीन अपनी संगठनात्मक क्षमता पहले ही साबित कर चुके हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन नबीन की नियुक्ति के पीछे कोई खास वजह या पाटा की कोई खास रणनीति है? विश्लेषक मानते हैं कि पाटा में ये बदलाव का दौर है और ये समय की जरूरत के हिसाब से उठाया गया कदम है। विजय त्रिवेदी और विनोद शर्मा दोनों ही मानते हैं कि पाटा जेनरेट्स चेंज यानि पीढ़ीगत बदलाव से गुजर रही है। पाटा में पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह नए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रादेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में पुराने नेताओं को हटाना और नए चेहरों को लाना पाटा की इसी रणनीति का हिस्सा है और नितिन नबीन का कायंकारी अध्यक्ष बनाया जाना इस कड़ी में अगला कदम है। पाटा नए नेतृत्व को आगे लाना चाहती है और ये नियुक्ति भी उसी दिशा में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाजपा में ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है जो किसी भी तरह से नरेन्द्र मोदी या अमित शाह के लिए चुनौती पेश न करें। विनोद शर्मा कहते हैं, नितिन नबीन की नियुक्ति हैरान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें अमित शाह की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है। किसी भी ऐसे नेता को मजबूत पद पर नहीं लाया जा रहा है जो आगे चलकर किसी भी तरह की शीर्ष नेतृत्व को चुनौती पेश कर सके। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो भाजपा और संघ को भी मंजूर हो। विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि नितिन नबीन का नाम उन चुनिन्दा लोगों में रहा होगा जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

एमआईसीई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय शहरों में कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना करेगा

डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना ही भारत को भविष्य के लिए तैयार वैश्विक एमआईसीई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी है: श्री सुमन बिल्ला

(जीएनएस)।

भारत सरकार का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, देश के मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन और एग्जीबिशन (एमआईसीई) टूरिज्म इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2026 से हितधारकों के साथ साझेदारी में स्वतंत्र निकायों के रूप में शहरों में कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

यह बात पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव और महानिदेशक श्री सुमन बिल्ला ने आज नई दिल्ली में इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) द्वारा आयोजित आईईआईए इवेंट-टेक और मारटेक समिट 2025 के उद्घाटन के दौरान कही।

सभा को संबोधित करते हुए श्री बिल्ला ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्य अपने अनूठे तरीकों से पर्यटन के अवसरों को खोल रहे हैं और अब भारत को वैश्विक एमआईसीई मैप पर प्रमुखता से स्थापित करने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे आइकॉनिक वेन्यू उपलब्ध होने और इन्क्रेडिबल इंडिया कैंपेन के तहत एमआईसीई पर्यटन को प्राथमिकता दिए जाने के साथ, हमारा उद्देश्य कई भारतीय शहरों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एमआईसीई डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है।

संस्थानिक सुधारों के महत्व पर जोर देते हुए, श्री बिल्ला ने कहा कि प्रोफेशनल सिटी एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना भारत की नेशनल एमआईसीई रणनीति का आधार स्तंभ बनेगी। ये ब्यूरो स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे, जो वैश्विक आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वित और विश्व स्तरीय सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना है।

प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए, श्री बिल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की योजना, मैनेजमेंट और डिलीवरी को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एमआईसीई क्षेत्र को उन्नत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल परिवर्तन समाधानों को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि अपने प्रमुख आयोजन स्थलों में स्मार्ट तकनीकों को एकीकृत करके, अनुमतियों और स्थानीय भागीदारों के नेटवर्किंग के लिए एक एकल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए, इस ढांचे का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक नेशनल बाजार में मजबूती से स्थापित होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) के अध्यक्ष, श्री सोराज धवन ने कहा कि आईईआईए भारत को दुनिया के शीर्ष पांच एग्जीबिशन मार्केट में शामिल करने के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का भारत का एमआईसीई बाजार, 2030 तक बढ़कर 103.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि इस वृद्धि को प्रेडिक्टिव इनसाइट्स जेनरेट करके और पूरे इकोसिस्टम में डिजिटल तौर-तरीकों को तेजी से अपनाकर, भारत एक भविष्य के लिए तैयार प्रदर्शनी और इवेंट गंतव्य के रूप में हासिल करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित प्रोफेशनल सिटी एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना की राष्ट्रीय रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ब्यूरो इवेंट आयोजकों के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेंगे, जिससे व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार होगा और इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इकोसिस्टम की समस्या का समाधान होगा।

श्री धवन ने आगे कहा कि सिटी एमआईसीई ब्यूरो स्थानीय भागीदारों और प्रोफेशनल सहायता का एक वेरिफाइड नेटवर्क प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय आयोजकों के लिए मार्केट में एंट्री के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रोफेशनलिज्म और प्रदर्शनी आयोजन के लिए बीआईएस मानकों को अपनाना, भारत में बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अगले पांच वर्षों के लिए भारतीय एमआईसीई उद्योग का रोडमैप विषय पर आयोजित एक गोलमेज शिखर सम्मेलन था। इसके साथ ही, आईईआईए की रणनीतिक रिपोर्ट "इंडिया एमआईसीई अपॉर्चुनिटीज ओवरव्यू (2025-2030)" का आधिकारिक विमोचन भी किया गया। यह रिपोर्ट वैश्विक एमआईसीई क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए संस्थानिक सहायता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है, जो प्रदर्शनी आयोजकों, आयोजन स्थल स्वामियों और सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आईईआईए "भारतीय व्यापार मेलों के प्रवेश द्वार" के रूप में कार्य करता है, जो प्रदर्शनी उद्योग को आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में आगे बढ़ा रहा है।

जैविक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाव

सरकार उर्वरकों की स्थिर कीमतें और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, साथ ही किसानों की सहायता के लिए जैविक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है

(जीएनएस)।

यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य साल 2018 से स्थिर बना हुआ है। इसी तरह, डीऐपी की कीमतें भी पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) से स्थिर हैं। इन कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए, भारत सरकार यूरिया और फॉस्फेटिक व पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों, दोनों पर सब्सिडी का बोझ खुद उठा रही है। यूरिया पर होने वाला वास्तविक खर्च प्राकृतिक गैस की कीमतों, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल की लागत और यूरिया के अंतरराष्ट्रीय आयात मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलता रहता है। वहीं, पीएंडके योजना के तहत, अधिसूचित उर्वरकों पर वार्षिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक निश्चित राशि तय की जाती है।

उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक बुवाई सीजन शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उर्वरकों की राज्यवार और महीने के अनुसार आवश्यकता का आकलन करता है। इस अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में की जाती है। उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। साथ ही, राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांग भेजकर आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए निमार्ताओं और आयातकों के साथ समन्वय बनाए रखें।

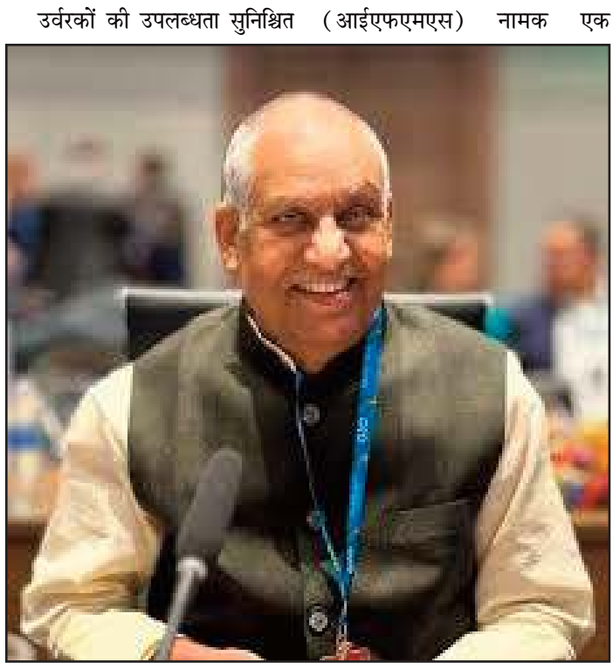

भारत सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑयल केक, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले और नैनो फर्टिलाइजर जैसे वैकल्पिक फर्टिलाइजर को नोटिफाई किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से और पूर्वोत्तर राज्यों में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ₹15,000 प्रति हेक्टेयर की राशि किसानों को जैविक खाद सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। वहीं, एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों में ₹46,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से ₹32,500 प्रति हेक्टेयर की राशि ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए निर्धारित है, जिसमें ₹15,000 की राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है। यह योजना 2014-15 से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी सभी खेतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) प्रदान करना है, ताकि उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। किसानों के खेतों की मिट्टी का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि कम से कम 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा सके। 2014-15 से अब तक देश भर में 25.61 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार और वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत शुरूआत से अब तक 1970 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही, देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन और 7,425 किसान मेलों या अभियानों का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

पीएम गतिशक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए 105वीं एनपीजी बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आज नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 105वीं बैठक बुलाई गई। बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुसार मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनपीजी ने 07 रेल परियोजनाओं और 01 सड़क परियोजना का मूल्यांकन किया जिससे पीएम गतिशक्ति के एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों और आर्थिक तथा सामाजिक केंद्रों के अंतिम छोर तक संपर्क के सरकार के समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन हो सके। पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप उम्मीद है कि इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी, यात्रा में लगने वाला समय कम होगा, और परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेंगे। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अपेक्षित प्रभावों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रोजेक्ट्स का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

रेल मंत्रालय

i. तीसरी और चौथी लाइन अराक्कोनम - रेनिगुंटा

रेल मंत्रालय ने बढ़ते यात्रियों की मांग को पूरा करने, लाइन क्षमता बढ़ाने, रेलगाड़ियों को समय पर चलाने और बढ़ती माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए अराक्कोनम और रेनिगुंटा के बीच 76.559 किमी लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह कॉरिडोर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जिलों को जोड़ने वाला है और "मिशन 3000 एमटी" और अत्यधिक घनत्व वाले यातायात मार्गों (अमृत चतुर्भुज) कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है।

इस प्रस्ताव से पूर्व उद्योग जगत से विचार-विमर्श किया गया है ताकि इस रेलवे लाइन का निर्माण ऐसे क्षेत्रों से हो

जहां से प्रमुख राजमार्गों और हवाई अड्डों से संपर्क सुनिश्चित हो सके, और उद्योग केंद्रों तथा प्रमुख ट्रांसपोर्ट नोड्स जुड़ सकें और मजबूत मल्टीमॉडल लिंक का लाभ मिले। माल लादने के लिए बेहतर संपर्क सड़कें ढुलाई की दक्षता को और मजबूत करेंगी। मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि यह परियोजना रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक निवेश है।

ii. इरोड - करूर सेक्शन के बीच दोहरिकरण

रेल मंत्रालय ने भीड़ कम करने, क्षमता बढ़ाने और यात्री तथा माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए संचालन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु में 66.67 किमी लंबी इरोड-करूर रेलवे लाइन के दोहरिकरण का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना कम दूरी वाले माल ढुलाई मार्गों को मदद करेगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय गतिशीलता को मजबूत करेगी।

इस कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यों के राजमार्गों, हवाई संपर्क और औद्योगिक केंद्रों से मौजूदा सड़क लिंक के साथ मजबूत जुड़ाव सहज मल्टीमॉडल परिवहन को सक्षम करेगा। लाइन को डबल करने से कोयला, स्टील, सीमेंट और ग्रेनाइट जैसी प्रमुख वस्तुओं की बिजली संयंत्रों और उद्योगों तक आवाजाही में भी सुधार होगा, जिसे लोडिंग पॉइंट्स तक पर्याप्त संपर्क सड़क मार्गों से मदद मिलेगी।

मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि यह परियोजना आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करते हुए संपर्क में सुधार करेगी, और तमिलनाडु के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होगी।

iii. गुंटाकल - बेल्लारी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने गुंटकल और बेल्लारी के बीच 45.92 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मौजूदा डबल-लाइन कॉरिडोर की क्षमता चार गुना हो जाएगी। यह परियोजना जेएसडब्ल्यू, कल्याणी स्टील्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट और केपीसीएल जैसे प्रमुख उद्योगों को सेवा देने वाले एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई और यात्री मार्ग पर क्षमता को बढ़ाने वाली होगी।

हुबली-गडग-बेल्लारी-गुंटकल मार्ग पर स्थित यह महत्वपूर्ण रेल खंड, उत्तर-पश्चिम कर्नाटक को सम्पूर्ण भारत के प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है। बेल्लारी, तोरनागल्लू, होसपेटे और गिनिगेरा खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ प्रमुख स्टील और पावर प्लांट हैं, ऐसे में बेहतर माल ढुलाई और दबाव कम होने से काफी लाभ होगा।

iv. गुंटकल - वाडी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरने वाली गुंटकल और वाडी के बीच 230 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना मौजूदा डबल-लाइन सेक्शन को चार लाइन वाला बना देगी, जिससे सबसे महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्गों में से एक इस खंड पर पर क्षमता बढ़ेगी।

यह कॉरिडोर नागपुर-बलहारशाह-कोठागुडेम बेल्ट से वाडी-गुंटकल-रेनिगुंटा एक्सिस के साथ ऊर्जा संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है और वाडी तथा तांदूर के बीच प्रमुख सीमेंट उद्योगों की सहायता करता है। इस विस्तार से रुकावटें कम होंगी, समय पर माल ढुलाई सुनिश्चित होगी, औसत गति में सुधार होगा, और यात्री और मालगाड़ियों दोनों के लिए अतिरिक्त रास्तों का विकल्प होगा।

v. सेलम-करूर-डिंडीगुल के बीच दोहरिकरण

रेल मंत्रालय ने यात्री भीड़ का दबाव कम करने, लाइन की क्षमता बढ़ाने और यात्री तथा मालगाड़ी के संचालन को आसान व तेज बनाने के लिए 159.26 किमी लंबे सेलम-करूर-डिंडीगुल रेलवे कॉरिडोर के दोहरिकरण का प्रस्ताव दिया है।

मेट्टूर थर्मल पावर प्लांट और स्टील, सीमेंट, कपड़ा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सेवा देने वाले एक प्रमुख ऊर्जा और औद्योगिक मार्ग के रूप में, अपग्रेड की गई लाइन से माल ढुलाई की लागत में काफी कमी आएगी, मालढुलाई दक्षता में सुधार होगा

सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि आयात और निर्यात की करती है निगरानी ।

(जीएनएस)।

सरकार देश के आयात और निर्यात गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है और घरेलू हितों की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार व्यापार नीतियों में संशोधन करती है। आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग सहित एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित है। यह आवश्यक कृषि उत्पादों पर कड़ी और नियमित निगरानी रखती है। उनकी उपलब्धता और बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करती है। यह समिति आयात में किसी भी वृद्धि पर भी नजर रखती है ताकि घरेलू उत्पादन, व्यापार या खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले रुझानों की तुरंत पहचान की जा सके। किसानों के हितों की रक्षा और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) कृषि उत्पादों के आयात की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्रालय/विभाग को आयात शुल्क या बंदरगाह प्रतिबंध जैसे उपायों की सिफारिश करता है। इसके अलावा सरकार कई योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। इनमें शामिल हैं:

- अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के अंतर्गत खरीद के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप;
- प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) का संचालन,
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बाजार संबंधी जानकारी और बफर स्टॉक संचालन और
- आय में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए पीएम-किसान जैसी इनपुट और आय सहायता योजनाएं।

इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य बाजार में व्यवधान के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

वाणिज्य विभाग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के अंतर्गत देश भर के अपने सदस्य निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विशेष रूप से किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के संबंध में एपीडा अपने पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से अच्छी कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से देश भर में लगभग 1080 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें निर्यातकों, किसान संगठन/परिवारिक संगठन/स्वयं सहायता समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। ताकि किसान समूहों को निर्यात आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा सके और उद्यमियों को संभावित निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अंत में एपीईडीए ने अपने सदस्य निर्यातकों एफपीओ और एफपीसी भागीदारी को विदेशों और भारत में आयोजित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड, भारत में आहार और गल्फ फूड आदि में आयोजित किया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) समुद्री क्षेत्र, ब्रिज एवं टनल इंजीनियरिंग, रक्षा लॉजिस्टिक्स और मल्टीमॉडल परिवहन योजना को आगे बढ़ाएगा - श्री अश्विनी वैष्णव

गति शक्ति विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी कोर्ट की दूसरी बैठक आयोजित

(जीएनएस)।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) ने नई दिल्ली के रेल भवन में अपनी दूसरी कोर्ट मीटिंग आयोजित की। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में श्री अश्विनी वैष्णव (रेलवे, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जीएसवी ने अपने परिचालन के तीन वर्षों के अंदर ही उद्योग-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ अभूतपूर्व प्रगति की है और देश के लिए एक आदर्श संस्थान बन गया है। रेलवे और विमानन क्षेत्रों पर अपना मजबूत ध्यान केंद्रित करते हुए, जीएसवी पुल और सुरंग इंजीनियरिंग, समुद्री क्षेत्र (जहाज निर्माण पर विशेष) के पाठ्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाएगा, रक्षा बलों और रेलवे के कौशल विकास में अधिक योगदान देगा और एकीकृत परिवहन योजना के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करेगा।

इस बैठक में शुभांगिनी राजे गायकवाड़ (बड़ौदा की राजमाता), श्री सतीश कुमार (अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड), लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह (सेना के उप प्रमुख), श्री अमरदीप सिंह भाटिया (सचिव, डीपीआईआईटी), श्री टीपी सिंह (डीजी-बीआईएसएजी), प्रोफेसर रजत मूना (निदेशक, आईआईटी जीएन), नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एमओआरटीएच, एल एंड टी, एएमडी जैसे प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि और गति शक्ति विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रोफेसर मनोज चौधरी (कुलपति, जीएसवी) ने प्रगति और स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी सदस्यों ने इतने कम समय में विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट प्रगति, विशेष रूप से उद्योग जगत के साथ सहयोग, रेलवे और रक्षा बलों के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण तथा सिविल सेवाओं के लिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा की। कोर्ट के सदस्यों ने पुल और सुरंग इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण, रेलवे, रक्षा क्षेत्र, रसद और आपूर्ति श्रृंखला में भविष्य की प्रगति के लिए कई सुझाव और सहयोगात्मक इनपुट दिए। सेना उप-प्रमुख ने भारतीय सेना की संबंधित अकादमियों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दायरे और विस्तार को बढ़ाने की वकालत की। विश्वविद्यालय इस वर्ष से भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) अधिकारियों के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं संचालित करेगा तथा अधिक चेयर प्रोफेसरशिप की स्थापना के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करेगा।

इस अवसर पर, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजी) और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने पीएम गति शक्ति को और गति देने के लिए समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जबकि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) ने गति शक्ति विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सुविधा के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। अतिरिक्त कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है और अतिरिक्त कैंपस के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

गति शक्ति विश्वविद्यालय, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय है, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा 2022 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत यह विश्वविद्यालय रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, समुद्री परिवहन, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच उद्यमिता बढ़ाने और उनके द्वारा संचालित उद्यमों से अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना कार्यान्वित कर रहा है

एकल स्थल पंजीकरण योजना से एमएसई को वित्तीय सहायता मिल रही है

विपणन सहायक योजना अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता प्रदान करती है; इस योजना से 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी लाभान्वित हुए हैं

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय-एमएसएमई अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में उद्यमिता बढ़ाने और अनुसूचित जाति/जनजाति संचालित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना-एनएसएसएचकार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की कई पहल की गई हैं, जिनमें क्षमतावर्धन कार्यक्रम; बाजार से संबद्ध करने, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कार्यशाला/जागरूकता अभियान, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर सहायता, एकल स्थल पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल पर नामांकन आदि शामिल हैं।

एनएसएसएचच योजना के विशेष विपणन सहायक घटक-एसएमएएस के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की क्षमता सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुगमता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को 36.41 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

एनएसएसएचच योजना के तहत विभिन्न लाभों की जानकारी देने के लिए; देश में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार और विशेष रूप से लक्षित दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सक्रियता से इस्तेमाल किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्र ने तमिलनाडु में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत 127 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 127.586 करोड़ रु की राशि जारी की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त है। यह अनुदान विधिवत निर्वाचित और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 9 जिला पंचायतों, 74 ब्लॉक पंचायतों और 2,901 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किया गया हैं।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की अनुशंसा करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किए जाते हैं। अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, किया जाएगा। प्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिनमें: (क) स्वच्छता और 'खुले में शौच मुक्त' स्थिति को बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए; और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CREDAI के राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @ 2047' को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उफ्एऊअक के राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @ 2047' को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे सामने 2047 तक हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम भारत के निर्माण और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाली एक बेंचमार्क पर पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में Next Gen इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए और कई प्रकार की नई पहल ने हमारे अर्बन डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ स्ट्रक्चर्ड किया बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले देशों के करीब पहुंचने के लिए एक रोडमैप भी बनाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट में कई पहल की गईं हैं और हर क्षेत्र की बाधाएं दूर करने का भी प्रयास किया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि CREDAI ने 20 लाख पौधे लगाकर 25 गांवों की 9 हजार एकड़ बंजर भूमि को फिर से हराभरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर डेवलपर को प्रोजेक्ट डिजाइन करते हुए थोड़ा ग्रीन एरिया को ध्यान में रखकर डिजाइन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर डेवलपर अपने हर क्रिएशन में बिल्डिंग बनते समय 10 अच्छे वृक्ष लगाने का प्रयास करता है तो यह बहुत अच्छा काम होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1999 से लेकर आज तक CREDAI ने हाउसिंग और हेबिटेट को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को सतत रूप से हासिल किया है। उन्होंने कहा कि CREDAI ने हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिक प्रथाओं को सर्वोपरि रखा और CREDAI के करण ही आज डेवलपर्स के काम को क्रेडिट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी बैलेंसशीट अच्छी होनी जरूरी नहीं है बल्कि हमारे काम के बारे में समाज में अच्छी साख होना भी बहुत जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि CREDAI ने भारत की निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक शीर्ष संस्था के रूप में इस क्षेत्र को स्ट्रक्चर्ड और स्वीकृत क्षेत्र बनाने का बहुत बड़ा काम किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि उफ्एऊअक आज 21 राज्यों के 230 शहरों में मौजूद है और लगभग 13 हजार डेवलपर्स का एक विशाल वट वृक्ष आज खड़ा है। उन्होंने कहा कि CREDAI ने अपने 25 साल पूरे कर इस क्षेत्र में अपनी जरूरत को भी साबित किया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में CREDAI ने अपने मानवीय चेहरे को भी उजागर किया है और लगभग 3 लाख से अधिक मजदूरों का भी प्रशिक्षण किया है। श्री शाह ने कहा कि हमें इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि मजदूर को किस क्षेत्र में स्किलिंग की जरूरत है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण बढ़कर 2035 तक 40 प्रतिशत तक हो जाएगा और 2047 तक देश की 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 50 प्रतिशत जिस शहरी क्षेत्र में रहती हो, तो उसके हाउसिंग की व्यवस्था का ज़िम्मा डेवलपर्स पर ही है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री शाह ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के अनुसार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन हाउसिंग का सैचुरेशन रेश्यो लाने के लिए अफोर्डेबल, इको-फ्रेंडली और बेहतर जीवन स्तर वाले हाउसिंग की दिशा में उफ्एऊअक को एक टीम बनाकर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समय आधारित अप्रूवल, ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटलाइज्ड रेकॉर्ड्स ने इस क्षेत्र में आर्किटेक्चर का एक विश्वास अर्जित किया है जिसे हम और तेज गति से आगे ले जाने वाले हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि फ्एफ्क्ष इस क्षेत्र के सुधार में एक structural breakthrough था जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कहा कि home buyers के हितों की रक्षा, निष्पक्ष लेनदेन और गुवत्तायुक्त निर्माण को सुनिश्चित करने की दिशा में RERA ने हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया है और 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि 29 राज्यों में अपील का प्राधिकरण भी गठित हो चुका है और 29 RERA प्राधिकरणों ने अपनी वेबसाइट्स भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख 55 हजार रियल एस्टेट परियोजनाएं फ्एफ्क्ष के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1 लाख 10 हजार डेवलपर्स भी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने GST का सबसे अधिक फायदा अगर किसी सेक्टर को पहुंचाया है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। उन्होने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी को 8 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया, आवास योजनाओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, सीमेंट पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, संगमरमर, ग्रेनाइट, रेत, चूना और ईंट पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, बांस फ्लोरिंग पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर एक बिल्डिंग बनने पर खर्च में नए सुधारों से 5 से 7 प्रतिशत की कमी की संभावना बन गई है। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत FDI को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी है और नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड भी जारी किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार इस सेक्टर के महत्व को समझती है और इसके माध्यम से हर व्यक्ति को अपना एक घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा हम CREDAI के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने बड़े डेवपृलपर्स से कहा कि क्या वे बड़ी योजना बनातेहुए साथ में ही एक कम लागत वाली हाउसिंग बनाना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे हम अपने सेक्टर की जरूरत के रूप में लेते हैं तो आने वाले दिनों में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 सहित इस क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी CREDAI को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, ऊर्जा सक्षम डिजाइन, वाटर रिसाइक्लिंग, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को हमें हउसिंग का न्यू नॉर्मल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजाइन का हिस्सा सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि रहने वाले के अच्छे जीवन के लिए इन सभा को अपने डिजाइन का हिस्सा बनाना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें लैंड मार्केट को अधिक पारदर्शी बनाना होगा और शहरों को अब लैंड बैंकिंग और सट्टात्मक होल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर का जाल बिछाने और सडकें बनाने से लेकर इको फ्रेंडली बिजली उत्पादन तक कई काम किए हैं जो शहर को रहने योग्य बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं।

निर्यात कार्गो एक्सप्रेस इच्छापुरी, गुरुग्राम से मुंद्रा पोर्ट तक चलाई जा रही है

सुनिश्चित रेल सेवा से निर्यात में तेजी और लागत प्रभाविता संभव हुई है

(जीएनएस)।

रेलवे, माल ढुलाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए निर्यात केंद्रित, सुनिश्चित ढुलाई सेवा, निर्यात कार्गो एक्सप्रेस गुरुग्राम के इच्छापुरी कंटेनर टर्मिनल से मुंद्रा बंदरगाह तक डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन के रूप में संचालित कर रही है। इससे पहले गुरुग्राम के गढ़ी से सुनिश्चित माल ढुलाई सेवा की 20 खेप संचालित हुई है। समय सारणीबद्ध रेल ढुलाई सेवा गुरुग्राम के इच्छापुरी से पहली बार

संचालित की जा रही है।

मुंद्रा बंदरगाह तक सुनिश्चित और समयबद्ध यह साप्ताहिक सेवा, माल की तेज, विश्वसनीय और अनुमानित समय में ढुलाई करेगी और निर्यातकों के लिए सहायक होगी, जिससे माल पहुंचने में विलंब और प्रचालन लागत में कमी आएगी।

उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल निर्यातकों के लिए सुनिश्चित माल ढुलाई सेवा संचालित कर रहा है। विशेष रूप से संचालित इस मालगाड़ी से न्यूनतम ठहराव, निर्बाध आवागमन, माल की तेज ढुलाई समय पर हो रही है। यह उच्च मूल्य निर्यात कार्गो के लिए विशेष रूप से बहुत उपयोगी है।

कपास पर आयात शुल्क और कम कीमत

(जीएनएस)।

सरकार को जानकारी है कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क की छूट देने ने घरेलू कीमतों में कमी आयी है। शुल्क में छूट मिलने बाद से, समतुल्य एस-6 कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो दिनांक 19.08.2025 मेंलगभग 79.15 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड थी वह दिसंबर 2025 में गिरकर लगभग 73.95 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड हो गईं, जो वैश्विक स्तर पर गिरावट को दशार्ता है। घरेलू स्तर पर भी कपास की कीमतों में इसी प्रकारर की कमी देखी गई है, जो लगभग 57,000 रुपये प्रति कैंडी से घटकर लगभग 52,500 रुपये प्रति कैंडी हो गई है। यह कमी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलावों के अनुरूप है। घरेलू कीमतें वैश्विक एवं घरेलू मांग-आपूर्ति की स्थितियों, विनिमय दर और गुणवत्ता संबंधी कारकों से प्रभावित होती हैं। 2024-25 मौसम के दौरान कपास का आयात कुल घरेलू खपत का लगभग 13.93 प्रतिशत था। छूट के बाद से कीमतें कम हो गई हैं, जो वर्तमान में प्रति कैंडी 51,500 रुपये से 52,500 रुपये के बीच हैं, जिससे उद्योग के लिए किफायती है जबकि एमएसपी-आधारित समर्थन किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से कपास किसानों को सहायता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाग मिलता है। 2025-26 मौसम के लिए, मध्यम रेशे वाली कपास के लिए एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो 2024-25 की तुलना में 589 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। किसानों को मजबूरी में कपास बेचने से रोकने के लिए, भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने 11.12.2025 तक एमएसपी के अंतर्गत 11 राज्यों के 149 जिलों में 570 खरीद केंद्रों के माध्यम से लगभग 31.19 लाख गांठें खरीदी हैं, जिनकी कीमत 13,492 करोड़ रुपये है।

भारत के घरेलू वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता एवं आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका से कपास का आयात बढ़ा है, जो भारत की लगभग 94 प्रतिशत कपास की खपत करता है। अगस्त-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, जिसमें 11 प्रतिशत आयात शुल्क की अस्थायी छूट प्रदान करने के बाद की अवधि भी शामिल है, अमेरिका से कपास का आयात उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है। कुल मिलाकर, भारत में कपास का आयात 2023-24 में 15.20 लाख गांठों से बढ़कर 2024-25 में 41.40 लाख गांठें रहा, जिससे मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिली। ये आयात विशेष प्रकार की कपास उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत के वस्त्र क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। एमएसपी द्वारा किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने एवं उचित लाभ सुनिश्चित किया जाता है।

डीडीडब्ल्यूएस ने 8 राज्यों के 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में स्थानीय भाषा में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया

केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने गुजरात के मेहसाना जिले के जाहिरपुरा गांव में गुजराती में लोगों से बातचीत की

राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने कर्नाटक के उडुपी जिले के कोडी गांव में कन्नड़ में लोगों से बातचीत की

स्थानीय भाषा में ग्रामीण समुदायों के साथ संवाद से 'जन भागीदारी' और समुदाय-नेतृत्व वाली जल व्यवस्था को मजबूती मिलती है

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने आज 'सुजल ग्राम संवाद' के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया । यह सहभागी जल शासन और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के समुदाय-नेतृत्व वाले कार्यान्वयन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है ।

इस वर्चुअल संवाद में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, सामुदायिक प्रतिभागियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं के साथ-साथ जिला कलेक्टर/उपायुक्त, जिला पंचायतों के सीईओ, डीडब्ल्यूएसएम अधिकारी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए ।

सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण में 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया , जो समुदायों और अधिकारियों दोनों की मजबूत भागीदारी को दशार्ता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों ने बड़े समूहों में संवाद में भाग लिया , जिनमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग समुदाय के सदस्य शामिल थे, जिनकी सामूहिक भागीदारी पंजीकृत संख्या से कहीं अधिक थी।

एक मेज पर बैठे पुरुषों का एक समूह - एआई द्वारा उत्पन्न सामग्री गलत हो सकती है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले 8 गांवों के साथ ग्राम स्तरीय वार्ता आयोजित की गई । केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के मेहसाना जिले के जहीरपुरा गांव के ग्रामीणों से गुजराती में बातचीत की , जबकि राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने कर्नाटक के उडुपी जिले के कोडी गांव के ग्रामीणों से कन्नड़ में बातचीत की ।

निफ्ट ने विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2026-27 बैच की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क घटाया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2026-27 बैच के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 6 जनवरी 2026 है (7 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक विलम्ब शुल्क के साथ) और परीक्षा की तिथि 8 फरवरी 2026 है।

सीबीटी और पेन-पेपर आधारित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर के 100 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी।

वर्ष 2026-27 बैच के लिए, शुल्क 3,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, जो ओपन, ओबीसी (एनसीएल) के लिए है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था।

योगी सरकार की बड़ी पहल, एमएसएमई के लिए एमआईसीई प्रोत्साहन योजना से मिलेगा वैश्विक मंच

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 के तहत ब्राण्ड यूपी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम

(जीएनएस)।

लखनऊ। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों (टरटए२) को देश-विदेश से जोड़ने के लिए पहली बार मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स (टकठए) प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 का हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ब्राण्ड यूपी को वैश्विक पहचान दिलाना है। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हाल ही में योगी सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से

2030 में इस योजना को पहली बार शामिल किया गया है। योजना के तहत टकठए कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रति विदेशी प्रतिभागी ₹7,000 या एक कार्यक्रम के लिए अधिकतम ₹6 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक टकठए ऑपरेटर एक वर्ष में अधिकतम दो कार्यक्रमों के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकेगा। इस योजना का लाभ वही टकठए इवेंट ले सकेंगे, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्य हों। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत टरटए श्रेणी के टकठए ऑपरेटर या इवेंट मैनेजमेंट इकाइयाँ, जो संबंधित विभागों और परिषदों में पंजीकृत हैं, योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से उत्तर प्रदेश को एक बड़े टकठए हब के रूप में पहचान मिलेगी, जिससे निवेश बढ़ेगा, निर्यात को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। कार्यक्रम से जुड़ा सामान, जैसे कैटरिंग और लॉजिस्टिक्स, प्रदेश के स्थानीय विक्रेताओं से ही लिया जाएगा। कार्यक्रम में कम से कम 100 प्रतिभागी होने चाहिए, जिनमें 25 प्रतिशत विदेशी नागरिक अनिवार्य हैं कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 60 दिन पहले निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसकी विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी। सभी आवेदनों की जांच के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अंतर्गत एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गई है, जिसमें निर्यात, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। योजना के तहत दावों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। स्वीकृत राशि ऊह्ळ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो उपलब्ध बजट के अनुसार होगी। यदि किसी इकाई द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या योजना का दुरुपयोग किया जाता है, तो पूरी राशि की वसूली की जाएगी और संबंधित इकाई को भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मानकों को ताक पर रखकर परोसा जा रहा जहर, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

(जीएनएस)।

लखनऊ। पिहानी के हरदोई कस्बे में संचालित हो रहे मांसाहारी होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिहानी के ए-वन रेस्टोरेंट सहित क्षेत्र के तमाम नॉन-वेज प्रतिष्ठान बिना किसी वैध मानक और सुविधाओं के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन होटलों की कमान अनुभवी हाथों के बजाय केवल कुर्सियों पर बैठे गैर-जिम्मेदार युवाओं के भरोसे है नगर पालिका परिषद से चंद कदम की दूरी पर उल्लंघन, आखिर मौन क्यों है जिम्मेदार? हैरानी की बात तो यह है कि ये होटल नगर पालिका परिषद कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन के मानकों की यहाँ रत्ती भर भी पालन नहीं हो रहा है। स्वच्छता और अतिक्रमण को लेकर सख्त दावे करने वाला नगर पालिका प्रशासन अपने ही दफ्तर के पास चल रहे इन अवैध होटलों को लेकर आंखें मूंदे बैठा है, जो उनकी कार्यप्रणाली पर

गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है कमर्शियल के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध प्रयोग, सुरक्षा खतरे में नियमों को ताक पर रखने का आलम यह है कि इन होटलों में कमर्शियल सिलेंडर के बजाय धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। सरकार और विभाग को राजस्व की चपत लगाने के साथ-साथ घनी आबादी के बीच घरेलू सिलेंडरों का यह व्यावसायिक उपयोग किसी बड़े अग्निकांड या हादसे का कारण बन सकता है। इसके बावजूद रसद विभाग और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। नियमों की बलि चढ़ता जनस्वास्थ्य आपको बताते चलें की पिहानी कस्बे में वर्तमान में दो से अधिक मुख्य नॉन-वेज होटल चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के एक भी मानक का पालन नहीं हो रहा है। न तो यहाँ साफ-सफाई की उचित व्यवस्था है और न ही खाद्य पदार्थों के रख-रखाव के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अनुभवहीन स्टाफ होटल प्रबंधन का पूरा दारोमदार केवल कुर्सियों पर बैठे युवाओं पर है, जिन्हें स्वच्छता और सुरक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। अवैध गतिविधियां: बिना किसी पंजीकरण, लाइसेंस या एनओसी (एनओसी) के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध संचालन जारी है सुविधाओं का अभाव: मानकों के विपरीत गंदगी के बीच तैयार हो रहा भोजन लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। पिहानी में अवैध रूप से फल-फूल रहा यह कारोबार किसी बड़ी बीमारी या दुर्घटना को दावत दे रहा है। क्या जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और रसद विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? कस्बे की जनता अब इस पर तत्काल छापेमारी और कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है।

पीलीभीत: क्रिसमस व न्यू ईयर पर शराब दुकानों का समय बढ़ा

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने क्रिसमस व नववर्ष उत्सव के मद्देनजर शराब की फुटकर दुकानों के समय में छूट की घोषणा की है। कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र (दिनांक 12.12.2025) के अनुसार, 24 दिसंबर (क्रिसमस पूर्व संध्या) व 25 दिसंबर (क्रिसमस) को तथा 31 दिसंबर (न्यू ईयर पूर्व संध्या) को दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी।

यह व्यवस्था उत्सवों के दौरान सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। डीएम ने बताया कि आबकारी विभाग इन निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा। जनता से अपील की गई है कि उत्सव मनाते समय शराब सेवन में संयम बरतें व कानून का उल्लंघन न करें।

पीलीभीत:-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकासखण्ड बिलसण्डा में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक हुई सम्पन्न

(जीएनएस)।

सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी, पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने ब्लाक बिलसण्डा सभागार में जरूरतमंदों को वितरित किए कम्बल

ग्राम पंचायत ईंटगांव व अमृताखास में संकुल स्तरीय समिति का फीता काटकर किया उद्घाटन

आवासीय वृद्धाश्रम मचवाखेडा का किया औचक निरीक्षण, वृद्धजनों को वितरित किए जूते व गर्म वस्त्र

पीलीभीत सूचना विभाग 19 दिसम्बर 2025/जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विकासखण्ड बिलसण्डा सभागार में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने उपस्थित ग्राम प्रधानों से वार्ता की, उनकी समस्याओं को सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय को बेहतर बनाया जाये तथा शासन द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंचायत सहायक के माध्यम से आवेदन कर पात्रों को दिलाया जाए। ग्राम सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के साथ बैठक कर योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ग्रामों में कहीं भी झोपडी न दिखे, पात्र व्यक्ति का नाम नोट कर सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराया जाये जिससे कि पात्रों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ

दिया जा सके। उन्होंने कहा कि 19 से 25 दिसम्बर तक अटल बिहारी वाजपेयी सप्ताह मनाया जायेगा, उक्त सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अच्छे शासन को बढ़ावा देने और जनता को बेहतर सेवाऐं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है वह अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाऐं।

जिलाधिकारी ने सभी को सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 05 लाख तक का ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना ताकि स्वरोजगार और उद्यमिता को बढावा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों को कम्बल एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों को वजन मशीन वितरित की। उन्होंने श्रम विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। श्रम विभाग में संचालित योजनाऐं-मातृत्व, शिशु एवं बालिका मद्द योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, शौचालय सहायता योजना, महात्मा गांधी पेन्शन योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामागार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना आदि के बारे में ग्राम प्रधानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपने अपने ग्रामों में ग्रामवासियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सोमवार को जिला अस्पताल में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं। जो दिव्यांगजन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है वह अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र विकास भवन के कमरा नम्बर 01 में जमा करा दें जिससे की उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण विभाग में संचालित बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना का लाभ पात्र अभिभावक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने कहा कि जनपद के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जाता है उक्त मेले में युवक/युवतियों रोजगार मेले में पहुंचकर प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति प्राप्त कर सकते है।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विकासखण्ड बिलसण्डा के ग्राम पंचायत ईंटगांव एवं विकासखण्ड बीसलपुर की ग्राम पंचायत अमृता खास में पहुंचकर दीनदयालय अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत संकुल स्तरीय समिति का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

एनएचआरसी ने म्सतना जिला अस्पताल में ब्लड ट्रैन्स्फ्यूशऩ के बाद छह बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में ब्लड ट्रैन्स्फ्यूशऩ के बाद छह बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है

आयोग ने पाया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है

रिपोर्ट में इस मुद्दे से निपटने के लिए उनके द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का विवरण शामिल होना चाहिए

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में ब्लड

ट्रैन्स्फ्यूशऩ के बाद कम से कम छह बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। बताया जाता है कि उनका थैलेसीमिया का इलाज चल रहा था। इसके लिए समय-समय पर ब्लड ट्रैन्स्फ्यूशऩ की आवश्यकता होती है। जनवरी से मई 2025 के बीच बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई और यह मामला अब सामने आया है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो इससे पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठता है। देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी ही घटनाओं की जानकारी भी आयोग को मिली है। इसलिए आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का विवरण दें।

16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य अधिकारी यह पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि क्या अन्य अस्पतालों में भी ब्लड ट्रैन्स्फ्यूशऩ की घटना घटी थी। अस्पताल ने इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) ने नई दिल्ली के द कुंज में राजस्थान के शिल्प संबंधी नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली कलानुभाव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के द कुंज मॉल में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर (जेसीकेआईसी) द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प, हथकरघा, कारीगरों द्वारा किए गए नवाचार और राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आजीविका कार्यक्रमों के तहत विकसित डिजाइन-पंजीकृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) की वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी भी मौजूद थीं। डॉ. एम. बीना, विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय (एमओटी); सुश्री पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव (फाइबर), एमओटी; श्री अशोक मल्होत्रा, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, एमओटी; श्री अनुज ओझा, संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), और आईआईटी जोधपुर के निदेशक डॉ. अविनाश अग्रवाल के साथ-साथ ओपीएसए और जेसीकेआईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

यह प्रदर्शनी कारीगरों के बनाए उत्पादों, कलानुभाव.इन, और धरोहर फिजीटल म्यूज़ियम जैसी आकर्षक पहलों को दिखाती है, जो जेसीकेआईसी के डिजाइन संबंधी नवाचारों, डिजिटल पहुंच और कारीगर समुदायों के क्षमता-विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।

द कुंज अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाना, बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाना और भारत के शिल्प क्षेत्र को सरकार के 'गांव से वैश्विक स्तर' तक ले जाने के विजन के अनुरूप ऊपर उठाना है।

उद्घाटन के दौरान, प्रोफेसर सूद ने मेहमानों को इस प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया और कहा, 'यह सहयोग दर्शाता है कि मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी) क्लस्टर विरासत को बचाते हुए कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए कैसे एक साथ काम कर सकते हैं।' उन्होंने सभी हितधारकों को ऐसे उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाने और सभी क्षेत्रों में कारीगरों की आजीविका को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

जेसीकेआईसी, कलानुभाव.इन और आकर्षक एआर/वीआर उपकरणों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी)-आधारित उपायों के जरिए कारीगरों की आजीविका को मजबूत करने पर ध्यान देता है और साथ ही डिजाइन पंजीकरण एवं भौगोलिक संकेत (जीआई) समर्थन के जरिए स्वदेशी शिल्पों के संरक्षण व वैश्विक पहचान को बढ़ावा देता है। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने जेसीकेआईसी को द कुंज में राजस्थान के पारंपरिक और तकनीक-आधारित शिल्प संबंधी नवाचार को प्रदर्शित करने हेतु एक खास जगह दी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी) पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) की सिफारिशों पर किया गया था। यह एक कंसोर्टियम-आधारित एवं मांग-संचालित मॉडल का पालन करता है ताकि एकीकृत बहु-हितधारक इकोसिस्टम बनाए जा सकें - जिसमें उद्योग, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षाविद, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, सरकारी निकाय और परोपकारी भागीदार एक साथ आएं ताकि आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के समर्थन में समन्वित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी)-आधारित उपायों के जरिए क्षेत्र-विशेष की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वर्तमान में, आठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी) क्लस्टर - दिल्ली-डीआरआईआईवी (2020), हैदराबाद-आरआईसीएच (2020), जोधपुर-जेसीकेआईसी (2020), पुणे-पीकेसी (2020), भुवनेश्वर-बीसीकेआईसी (2021), बेंगलुरु-बीईएसटी (2022), उत्तरी क्षेत्र-पीआई-आरएएचआई (2023), और सबसे नया विजाग-एएमटीजेड (2024) में स्थापित हैं।

राष्ट्रव्यापी आदिवासी विकास को गति देने के लिए श्री जुएल ओराम के नेतृत्व में आदिवासी सांसदों ने हाथ मिलाया

(जीएनएस)।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने गुरुवार को जनजातीय संसदों और मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय वार्ता का नेतृत्व किया। इस वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को गति देने के लिए निर्वाचित जनजातीय नेतृत्व के सामूहिक संकल्प पर जोर दिया गया।

विस्तृत वक्तव्य पढ़ते हुए श्री ओराम ने बताया कि यह संवाद आदिवासी नागरिकों के समावेशन, सशक्तिकरण और गरिमा के प्रति सांसदों - मंत्रियों की साझा जिम्मेदारी और एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि आदिवासी सांसद न केवल नीतिगत वकालत में बल्कि कल्याणकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्री ओराम ने प्रधानमंत्री-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और वन अधिकार अधिनियम के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो सामूहिक रूप से सघन विकास के माध्यम से आदिवासी और

पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, सिकल सेल रोग का उन्मूलन, वन धन पहलों के माध्यम से आजीविका के अवसरों का विस्तार और वन अधिकारों की मान्यता के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया।

इस संवाद ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में आदिवासी सांसदों के सामूहिक प्रयास की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य देश भर में आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

इस संवाद में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री. दुगार्दास उइके, श्रीमती सावित्री ठाकुर - धार (एमपी), श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाई-दमन और दीव, श्री सुखदेव भगत-झारखंड, श्री राजकुमार रोएत-राजस्थान, श्री मनोज तिग्गा-पश्चिम बंगाल, श्री अमरसिंग तिस्सो-असम, श्री प्रदीप पुरोहित-(बारगढ़) ओडिशा, श्री बलभद्र माझी- (नबरंगपुर) ओडिशा, श्री नाबा चरण माझी- (मयूरभंज) ओडिशा, श्रीमती मालविका देवी-(कालाहांडी) ओडिशा शामिल रहे। इसके अलावा, जनजातीय कार्य सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा, संयुक्त सचिव श्री. अनंत प्रकाश पांडे, अपर सचिव श्री. मनीष ठाकुर, आयुक्त एनईएसटीएस श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव और अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस संवाद में नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जमीनी स्तर की समझ का एक दुर्लभ संगम देखने को मिला, जिसमें आदिवासी सांसदों ने कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने, समन्वय को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस सामूहिक प्रयास ने आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और गरिमा के प्रति संसद की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।